ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जमीन पर उतरेंगे 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव : योगी

मुख्यमंत्री ने हर निवेशक के साथ संवाद करने की दी नसीहत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआइएस) में हुए निवेश करारों को धरातल पर उतारने की प्रयासों में जुटी योगी सरकार ने अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तवों को जमीन पर उतारने का लक्ष्य तय किया है।

शुक्रवार को अपने आवास पर बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ • सूचना विभाग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने आवास में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ विशेष बैठक में जीबीसी का नया लक्ष्य तय करते तैयारी तेज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआइएस के दौरान हुए एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर किए गए प्रयासों के तहत आठ हजार से अधिक परियोजनाएं जमीन पर उतरने को तैयार हैं। हमें न्यूनतम 15 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना चाहिए। बैठक में जीबीसी के आयोजन को लेकर तिथि पर सहमति नहीं बनी। हालांकि माना जा रहा है कि अब यह आयोजन अगले वर्ष फरवरी में होगा।

फरवरी, 2023 में आयोजित जीआइएस के दौरान प्रदेश सरकार को देश-विदेश के निवेशकों से करीब 35 लाख करोड़ रुपये के

जीबीसी के लिए तय किया लक्ष्य, जीआइएस के बाद भी मिल रहे निवेश प्रस्ताव, अब तक 39.52 लाख करोड़ के हुए एमओयू

निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। यह आंकड़ा अब बढ़कर 39.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। निवेश प्रस्तावों की कड़ी आगे बढ़ने से उत्साहित राज्य सरकार ने 13 लाख करोड़ रुपये के जीबीसी लक्ष्य को संशोधित करते हुए अब 15 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्राप्त हुए 39.52 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। इससे 1.10 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। निवेशकों ने मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ईवी, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तकरीबन हर क्षेत्र में रुचि दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए निवेशकों से लगातार संवाद बनाए रखने की नसीहत दी।

कहा, उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान हो, एनओसी देने में देरी नहीं होनी चाहिए। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्री के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश प्रस्ताव की तत्काल समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सहित सभी सेक्टोरल नीतियों का लाभ निवेशकों को बिना विलंब मिलना चाहिए। उन्होंने गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहन देने के क्रम में प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति जल्द जारी करने के भी निर्देश दिए।

देश की महत्वपूर्ण खबरें
www.jagran.com पर पढ़ें